वर्ष : 05 अंक : 03
गाजियाबाद, गुरुवार 23 अप्रैल 2026
पृष्ठ-6 मूल्य : दो रूपये
RNI No - UPHIN/2022/84480
E-mail: swastiksaharanews@gmail.com
www.swastiksahara.com

मछली एवं अतिथि, तीन दिनों के बाद दुर्गन्धजनक और अप्रिय लगने लगते हैं।

नई दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में गरजे मुख्यमंत्री

कांग्रेस-सपा महिला विरोधी: सीएम योगी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दल महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा के इतिहास व उनके कारनामों को महिला विरोधी बताया। उन्होंने बुधवार शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का स्वतः अधिकार बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को कानून बनाने में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के इतिहास और परंपरा में मातृशक्ति सदैव प्रतिष्ठित रही है। उन्होंने भगवान राम को कौशल्यानंदन और प्रभु कृष्ण को यशोदानंदन कहे जाने का उदाहरण दिया। श्रीराम में श्री शब्द माता सीता के लिए है और सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा भी पहले माता सीता का नाम जोड़कर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण की धरा मथुरा-वृंदावन में हर संबोधन राधे-राधे से शुरू होता है। काशी में नमः पार्वती पतये का उद्घोष होता है और गंगा जी को मां गंगे कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी गरिमा को हर स्तर पर सम्मान देने का काम शुरू हुआ है।

विस्तृत खबर पृष्ठ 6 पर...

राहुल बाबा की संगत में बिगड़ी खरगे की भाषा, पीएम मोदी पर बयान से भड़के अमित शाह

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने की कड़ी आलोचना की और खरगे की इस भाषा का कारण राहुल गांधी के नकारात्मक प्रभाव को बताया। एक चुनावी रैली में बोलते हुए शाह ने कहा कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद का खात्मा किया, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल बाबा के आसपास रहने से खरगे जी की भाषा भी बिगड़ने लगी है। राहुल गांधी को सीधे संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सुनिए, राहुल बाबा आप मोदी जी पर जितनी गालियां बरसाएंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही

अधिक गौरव से खिलेगा, और हम राज्य में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लाएंगे, जिससे तीन तलाक और चार विवाह करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। यह विवाद मंगलवार को तमिलनाडु चुनाव प्रचार के अंतिम दिन खरगे के भाषण के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने एआईएडीएमके के भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी को समानता में विश्वास न करने वाला आतंकवादी बताया, जिससे राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। खरगे ने बाद में स्पष्ट किया कि मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा वे ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों को आतंकित कर रहे हैं और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। भाजपा ने खरगे की टिप्पणियों की निंदा की और माफी की मांग करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा और उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ''आतंकवादी'' संबंधी टिप्पणी के लिए उनके (खरगे) खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को 40 हजार, 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 40,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता शामिल है। इसे प्रमुख मतदाता वर्गों को एकजुट करने का सीधा प्रयास माना जा रहा है। पार्टी कार्यकताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार मुफ्त बिजली और महिलाओं को लक्षित नकद सहायता के माध्यम से परिवारों को पर्याप्त आर्थिक राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 40,000 रुपये की वार्षिक सहायता समाजवादी पेंशन योजना के संशोधित संस्करण के माध्यम से दी जाएगी, जो पहले के सहायता कार्यक्रमों की तुलना में काफी अधिक होगी।

गौरतलब है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम विशेष रूप से महिलाओं और निम्न-आय वर्ग के लोगों को लक्षित करता है, जिन्होंने हाल के चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाई है। यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर महंगाई, बिजली आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विफलताओं का आरोप लगाते हुए उसे निशाना बनाया। उन्होंने बिजली वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार पर विशेष रूप से स्मार्ट मीटरों के कार्यान्वयन को लेकर चिंता जताई।

समाजवादी पार्टी प्रमुख की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की गई पहल से मुफ्त योजनाओं पर बहस और तेज हो गई है, और आलोचक इन वादों की वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि नकद हस्तांतरण योजनाएं कई राज्यों में चुनावी रूप से कारगर साबित हुई हैं, लेकिन पर्याप्त राजस्व नियोजन के बिना ये राज्य के वित्त के लिए चुनौतियां भी खड़ी करती हैं। राजनीतिक रूप से, यह घोषणा समाजवादी पार्टी द्वारा हालिया चुनावी हार के बाद खोई हुई जमीन वापस पाने और महिला मतदाताओं के बीच भाजपा की मजबूत पकड़ का मुकाबला करने के प्रयास को दर्शाती है। 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, ऐसे में वादों को समय से पहले जारी करना उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले में माहौल को अपने पक्ष में करने की आक्रामक रणनीति का संकेत देता है।

ममता राज में 7000 इंडस्ट्रीज बंद! योगी बोले- टीएमसी ने 30 लाख युवाओं की नौकरी छीनी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि उसके शासन में पश्चिम बंगाल में उद्योगों का भारी पतन हुआ है और उसने एक राष्ट्रीय आर्थिक अगुआ के तौर पर अपनी जगह खो दी है। बड़ा बाजार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य, जो कभी उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब वर्षों के कुशासन के कारण पिछड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान 7,000 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गईं।

उन्होंने कहा कि बंगाल, जो कभी

कई सेक्टरों में सबसे आगे था, अब सबसे नीचे पहुँच गया है और साथ ही यह भी जोड़ा कि हजारों एमएसएमई यूनिट्स भी बंद हो गई हैं, जिससे लगभग 30 लाख युवाओं की नौकरियाँ चली गई हैं। उन्होंने दावा किया कि इस गिरावट ने राज्य को एक ऐसी जगह में बदल दिया है, जिसे उन्होंने इंडस्ट्रीज का कब्रिस्तान बताया। योगी आदित्यनाथ ने भाषा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी चिंता जताई, और आरोप लगाया कि बंगाली परंपराओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

टैगोर की विरासत को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया

नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के जोरासांको स्थित पैतृक घर का ज़िक्र करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ऐतिहासिक घर के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसे उन्होंने टैगोर की विरासत का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर भारत माता और महान सांस्कृतिक हस्तियों की झलक दिखनी चाहिए, न कि राजनीतिक प्रदर्शन।

बंगाल में राजनीतिक बदलाव की मांग

'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष का ज़िक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को 'अपनी खोई हुई शान वापस पानी होगी' और दावा किया कि ऐसा केवल सरकार बदलने से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को विकास लाने और उद्योगों को फिर से ज़िंदा करने के लिए, जिसे उन्होंने 'डबल-इंजन सरकार' कहा, उसकी जरूरत है।

केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पुष्कर धामी ने की पहली पूजा

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में आज पूरे रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ प्रवेश हुआ, जिसमें भारत और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए धाम का दौरा किया। समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों का पाठ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली प्रार्थना की और राज्य की जनता की खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। कई श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखकर अपार आस्था और आनंद व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम, चार धामों के साथ, उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित तीर्थयात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं ताकि किसी भी तीर्थयात्री को असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल उपलब्धता, स्वच्छता और सुरक्षा उपायों में उच्च मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया।

बंगाल चुनाव: केजरीवाल का ममता को फुल सपोर्ट, कहा- 'दीदी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहीं, पीएम मोदी हारेंगे'

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने फोन पर उनसे बात की और पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि अभी ममता दीदी से फोन पर बात हुई। मैंने उन्हें पूरी एकजुटता और समर्थन दिया। वह सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक

है। मोदी जी हारेंगे, चाहे उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी संस्थानों का दुरुपयोग किया हो। केजरीवाल की ये टिप्पणियां पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आई हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कड़ी टक्कर दे रही है। उनकी ये टिप्पणी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर में प्रस्तावित रैली की अनुमति रद्द करने के एक दिन बाद आई है, जिससे तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यह फैसला 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले आया है, जिसमें भवानीपुर भी शामिल है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई।

चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, खरगे के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधमंडल ने बुधवार को यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर शिकायत की तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में श्री रिजिजू के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और श्री ओम पाठक और कई अन्य नेता शामिल थे।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद श्री रिजिजू ने कहा, ' आज, भाजपा के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हम भारी मन और गहरी नाराजगी के साथ इन अधिकारियों मिले।

हीट वेब: उत्तर भारत में आग बरपाएगा सूरज

दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में भीषण लू की चेतावनी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में बताया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक सहित

तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, आईएमडी द्वारा जारी बयान के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में रातें गर्म रहने की संभावना है। दिल्ली के लिए, आईएमडी ने 24 अप्रैल को मुख्य रूप से साफ आसमान और कुछ स्थानों पर लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। नई दिल्ली में बुधवार से शुक्रवार तक लू चलने की आशंका है, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थिति को देखते हुए, आईएमडी ने दिल्ली के लिए दिन भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लू चलने की आशंका जताई गई है।

अधिकतम तापमान 42त्ड से 44त्ड के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से काफी अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 22त्ड से 24त्ड के बीच रह सकता है। हवाएं हल्की रहने की संभावना है, जो मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से चलेंगी। जलमार्ग प्रबंधन विभाग ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान से गर्मी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, विशेषकर शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों जैसे संवेदनशील समूहों में। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे लंबे समय तक धूप में न रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ओआरएस, नींबू पानी और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें।

तमिलनाडु चुनाव: सीएम स्टालिन का मास्टरस्ट्रोक, एक करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए परिवार की महिला मुखिया को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इस योजना का नाम 'कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम' है। इस योजना के माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। इस योजना को लॉन्च करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि महिलाओं की भूमिका को हमेशा कम समझा जाता है। महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे में यह योजना महिलाओं को सशक्त करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत

आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को प्रति साल 3600 यूनिट से अधिक बिजली खर्च न हो। वहीं योजना का लाभ लेने वाली महिला की उम्र 21 साल होना जरूरी है। 15 सितंबर 2002 से पहले जन्मी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के लिए फैमिली कार्ड रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिनका फैमिली कार्ड बना है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक कार्ड पर एक ही लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया को इस योजना के तहत 1 हजार रुपए मिलेंगे। जिस महिला का नाम परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज होगा, उसके खाते में हर महीने 1 हजार रुपए का भुगतान होगा।

उल्टी-दस्त से सात साल की बच्ची की मौत

गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है।

बुधवार को गर्मी से बिगड़ी तबीयत के चलते विजयनगर क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची हिमांशी को उल्टी-दस्त और बेहोशी की हालत में जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर फैल गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गर्मी से संबंधित बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उल्टी-दस्त, बुखार, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन और आंखों में जलन की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।

जिलाधिकारी ने किया गोविन्दपुरम अनाज मंडी का औचक निरीक्षण

घटतौली से सम्बंधित ना हो कोई कमी, किसानों की सुविधा का रखा जाएं विशेष ध्यानः रविन्द्र कुमार मॉदड़

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गोविन्दपुर अनाज मण्डी में व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से मंडी प्रशासन और कर्मचारियों में हलचल मच गई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और मंडी की समग्र व्यवस्था का वास्तविक आकलन करना था।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले किसानों के रुकने की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि दूर-दराज से आने वाले किसानों के लिए ठहरने की पर्याप्त और साफ-सुथरी व्यवस्था है या नहीं। इसके बाद उन्होंने मंडी परिसर में यातायात और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने और अनावश्यक जाम से बचने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने घटतौली जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तौल कांटों की जांच भी कराई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यापारी या कर्मचारी द्वारा घटतौली करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कहा कि तौल प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके।

इसके अलावा, उन्होंने विक्रेता किसानों के लिए खानपान की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को स्वच्छ और उचित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाए। शौचालय और विश्राम स्थलों की स्थिति का भी जायजा लेते हुए उन्होंने साफ-सफाई और नियमित रखरखाव के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने मंडी की व्यवस्थाओं के साथ-साथ अभिलेखों की भी गहन जांच की। उन्होंने मेंटेनेंस रजिस्टर, खाता बही, गेट रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए उनके सही तरीके से संधारण और अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट किए जाएं और उनमें किसी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि न हो। उन्होंने कहा कि अभिलेखों का सही रख-रखाव पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के इस पहलू से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन मंडी की व्यवस्थाओं को न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि दस्तावेजी स्तर पर भी मजबूत और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने खाद्यान्न भण्डारण व्यवस्था का भी बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने गोदामों में रखे गए अनाज की गुणवत्ता, रख-रखाव और सुरक्षा मानकों की स्थिति की जांच की। इस दौरान यह देखा गया कि अनाज को नमी, कीटों और अन्य नुकसान से बचाने के लिए निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भण्डारण स्थलों की नियमित सफाई और फ्यूमिगेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनाज सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि गोदामों में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खाद्यान्न खराब न हो। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी मॉदड़ ने मंडी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी और किसान हित में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। इस औचक निरीक्षण से मंडी में व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश गया है।

सीडीओ अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पंचायत भवन निर्माण, संचालन, पंचायत सहायकों द्वारा पंचायत सचिवालय से दी जाने वाली ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को प्रदान किया जाना, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के किनारे साफ सफाई, ग्राम पंचायतों के मुख्य मार्गों तथा अन्य शासकीय स्थलों की स्वच्छता हेतु कराए जाने वाले कार्यों, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, ऑडिट परिपालन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ओडीएफ प्लस ग्रामों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सामुदायिक शौचालयों का संचालन आदि समस्त संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

इस वर्ष होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम वन विकसित किए जाने के निर्देश दिये गए थे, जिसके सापेक्ष अभी तक 35 ग्राम पंचायतों में स्थल चिन्हित किए गए हैं। उनके द्वारा निर्देश दिए गए है कि मंदिरों, अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तान, तालाब के किनारों या अन्य ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर मियावाकी पद्धति से एक ही जगह अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। लगाये जाने वाले पोधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्ययोजना भी तैयार कर ली जाए। इस वर्ष जनपद में 08 अंत्येष्टि स्थल, 04 पंचायत भवन, 02 पंचायत उत्सव भवन, 03 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट एवं 02 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने है। 2399 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण भी इस वर्ष कराया जाना है। उनके द्वारा निर्देश दिए गए है कि इन भवनों है हेतु अगले 03 दिन में स्थल चिन्हित करते हुए उसका प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति शौचालय से वंचित न रहे। शत प्रतिशत ग्राम वासियों की फैमिली आईडी तथा किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य पूर्ण किया जाए। समस्त जन प्रतिनिधियों के यहाँ पर पीएम सूर्या घर योजना के अंतर्गत प्लांट अवश्य लगवाया जाए। बैठक में ज़िला पंचायत राज अधिकारी, जाहिद हुसैन, समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा प्रतिभाग किया गया।

9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा हजारों मामलों का समाधान

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निदेर्शानुसार आगामी 9 मई, शनिवार को जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कचहरी गाजियाबाद परिसर में आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा बनौधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद सिंह रावत के निर्देशन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण कराना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी एवं फौजदारी के लघु मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटरयान चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार वाद तथा दाम्पत्य विवादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं या जो न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व विवाद का समाधान चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र, सस्ता और स्थायी समाधान प्राप्त करें।

प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत में होने वाला समझौता अंतिम माना जाता है और इसमें किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

लू का अलर्ट, तापमान 40 पार जाने की आशंका प्रशासन ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में बढ़ती गर्मी और संभावित लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ भट्ट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी चेतावनी का हवाला देते हुए बताया कि आगामी पांच दिनों तक प्रदेश में उष्ण लहर चलने की संभावना है और जनपद का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गाजियाबाद में तापमान 44.48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की स्थिति में हीटवेव घोषित की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान के साथ बढ़ी हुई आर्द्रता और प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी, ऐठन, चक्कर आना और गंभीर मामलों में जान का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान के कारण अर्बन हीट आइलैंड की स्थिति बनने की संभावना रहती है, जिससे गर्मी का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्तियों, मजदूरों, कमजोर एवं निराश्रित लोगों को लू से अधिक खतरा रहता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला आपदा विशेषज्ञ वैभव पाण्डेय द्वारा जारी एडवाइजरी में नागरिकों से अपील की गई है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें तथा धूप में निकलते समय सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें। शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें और यात्रा के दौरान पानी साथ रखना जरूरी बताया गया है। प्रशासन ने लोगों को ओआरएस घोल, नारियल पानी, लस्सी, छाछ, नींबू पानी, चावल का पानी और आम पन्ना जैसे घरेलू पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। साथ ही रेडियो, टीवी और समाचार माध्यमों से मौसम की जानकारी लेते रहने तथा कमजोरी या चक्कर महसूस होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने को कहा गया है। घरों को ठंडा रखने के लिए पर्दे और शटर का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भीषण गर्मी के दौरान भारी श्रम वाले कार्यों से बचें, अधिक प्रोटीन युक्त या बासी भोजन का सेवन न करें तथा शराब, चाय, कॉफी और काबोर्नेटेड पेय पदार्थों से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये शरीर में निर्जलीकरण बढ़ाते हैं।

दोपहर के समय खाना पकाने से बचने और रसोईघर को हवादार बनाए रखने के लिए खिड़की व दरवाजे खुले रखने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि लू को हल्के में न लें और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निदेर्शों का पालन कर स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में मॉडिफाइड साइलेंसर (तेज/अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साइलेंसर) के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं आमजन को राहत प्रदान करना है।

अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों की पहचान की गई जिनमें अवैध/मॉडिफाइड साइलेंसर लगे पाए गए। कुल 3 वाहनों का चालान किया गया तथा 2 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर मौके पर ही हटवाए गए। आवश्यकतानुसार कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे आमजन, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों एवं मरीजों को गंभीर असुविधा होती है। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में मानक (स्टैंडर्ड) साइलेंसर का ही प्रयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

जनता दर्शन में जिलाधिकारी सख्त, शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जन समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जनता दर्शन के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े प्रार्थना पत्र और शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी मामलों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार जनता दर्शन और जनसुनवाई कार्यक्रम की सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश से लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जन शिकायतें अनिवार्य रूप से सुनी जाएं और इस दौरान वे जूम प्लेटफॉर्म पर भी लाइव उपलब्ध रहें। जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया। साथ ही जूम के माध्यम से संबंधित विभागीय अधिकारियों से सीधे संपर्क स्थापित कर उन्हें शिकायतों की जानकारी देते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ जरूरतमंद नागरिकों के राशन कार्ड से संबंधित आवेदन भी मौके पर भरवाए गए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जनता दर्शन कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी सिटी विकास कश्यप भी उपस्थित रहे और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

अग्निशमन सेवा सप्ताहः 65 स्थलों पर पहुंचकर 7200 लोगों को दी अग्नि सुरक्षा की जानकारी

स्कूल, अस्पताल, उद्योग, मॉल और आवासीय क्षेत्रों में मॉक ड्रिल व सुरक्षा प्रशिक्षण

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। अग्निशमन एवं आपात सेवा गाजियाबाद द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में चले इस अभियान ने पूरे जनपद में सुरक्षा जागरूकता की मजबूत मिसाल पेश की। अभियान की शुरूआत 14 अप्रैल को फायर स्टेशन वैशाली से अग्निशमन वाहनों की जागरूकता रैली के साथ हुई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय केशव कुमार चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और नागरिकों को अग्नि सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया। अग्निशमन सप्ताह के दौरान गाजियाबाद के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों, मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा आवासीय क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न शिक्षण संस्थानों जैसे नेहरू वर्ल्ड स्कूल शास्त्रीनगर, सुशीला मॉडर्न स्कूल दयानंद नगर, सन वैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली, पीएनएन मोहन स्कूल वसुंधरा, नेशनल पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर तथा केएन मोदी ग्लोबल पब्लिक स्कूल मोदीनगर में विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

इसी क्रम में गौर सेंट्रल मॉल, शॉप्रिक्स मॉल वैशाली, शिप्रा मॉल इंदिरापुरम सहित प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में मॉक ड्रिल आयोजित कर आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकासी, अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग तथा प्राथमिक बचाव उपायों का प्रदर्शन किया गया।

अर्थ डे पर नगर निगम ने चलाया महा अभियान, प्लांटेशन के साथ-साथ प्रदूषण मुक्त शहर का भी दिया संदेश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शहर में अनेको कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमें विशेष रूप से पांचों जोन अंतर्गत पार्कों में भव्य रूप से प्लांटेशन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज के नेतृत्व में लगभग 5000 से अधिक पौधे लगाए गए इंदिरापुरम, मोहन नगर, लोहिया नगर, विजयनगर, कवि नगर, वैशाली के पार्कों में प्लांटेशन किया गया जिसमें कई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भी प्रतिभाग करते हुए, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया।

प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज द्वारा बताया गया गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस पर प्लांटेशन के कार्यक्रम आयोजित हुए लोहिया नगर में कंपोजिट विद्यालय लोहिया नगर की छात्राओं द्वारा पौधे लगाए गए।

इसी क्रम में अन्य 50 स्थान पर पौधारोपण किया गया, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा हरा भरा बनाए रखने के लिए जन-जन को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया गाजियाबाद नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की टीम द्वारा ट्रैफिक सिगनलों पर रेड लाइट ऑन होने पर इंजन बंद करने के लिए भी अपील की गई शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यात्रियों को जागरूक किया गया, मैस्कॉट के माध्यम से भी सिग्नल ऑन इंजन बंद का संदेश दिया गया, वेस्ट तो आर्ट के अंतर्गत रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल को बढ़ावा देते हुए एक्टिविटी कराई गई।

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पृथ्वी को हरा-भरा बनाने के लिए प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया शहर वासियों को भी अधिक से अधिक प्लांटेशन करने के लिए जागरूक किया गया। शहर को प्लास्टिक मुक्त कचरा मुक्त बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए माननीय पार्षदों की उपस्थिति में गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए जन-जन को स्वच्छता और पर्यावरण बचाओ प्रदूषण हटाओ का संदेश दिया' लोहिया नगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्षद कुलदीप व निगम अधिकारियों ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया, कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित निगम के कार्यक्रमों में सहयोग किया गया।

इंदिरापुरम की टीएनटी टावर सोसायटी में 29वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित टीएनटी टावर सोसायटी में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बेटी के घर आई एक महिला की 29वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। महिला पहले नीचे खड़ी कार पर गिरी और फिर जमीन पर जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि ऊंचाई से गिरने के कारण महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। घटना से पूरी सोसायटी में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार टीएनटी टावर सोसायटी, पुस्ता रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के सामने रहने वाली भावना के घर उनकी मां फूलवती दो दिन पहले आई थीं। मंगलवार देर रात करीब तीन बजे सोसायटी परिसर में एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला पहले सोसायटी परिसर में खड़ी एक कार की छत पर गिरी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद वह नीचे जमीन पर आ गिरी। ऊंचाई अधिक होने के कारण घटना स्थल पर काफी खून फैल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए।

सशक्त नारी, समृद्ध समाज, महिला आरक्षण से नया आगाज: पंकज चौधरी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सपा-कांग्रेस को घेरा, भाजपा ने गिनाईं उपलब्धियां

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भाजपा नोएडा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा व कांग्रेस द्वारा किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध तथा परिवारवाद के संरक्षण पर हमला करते हुए कहा कि महिलाएं संभालेंगी जिम्मेदारी, तो खत्म होगी पारिवारिक यारी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि नोएडा सिर्फ.उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे तेज प्रगति करने वाला शहर है। इस औद्यौगिक नगरी में हजारों कंपनियां, उद्योग धंधे मौजूद हैं। राज्य की तरक्की का रास्ता इस शहर से होकर गुजरता है। ये तरक्की सिर्फ.पुरुषों की बदौलत नहीं है। इस तरक्की में आधी भागीदारी महिलाओं की भी है।

श्री चौधरी ने जोर देते हुए कहा की 2017 से पहले के हाल से हम सब वाकिफ हैं, शहरों में खुलेआम छेड़खानी आम बात थी। बहन- बेटियां बाहर निकलती थीं, तो परिवार वाले तब तक चिंतित रहते थे, जबतक वह सकुशल वापस न आ जाएं। गुंडे, माफिया, अपराधियों को लाल टोपी वालों का नैतिक समर्थन हासिल था और गुंडों के सामने प्रशासन नतमस्तक रहता था। पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में आए बदलाव पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार बनी, तब बदलाव दिखना शुरू हुआ।

शहरों में बहन- बेटियों और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। प्रशासनिक जवाबदेही और सतत निगरानी बढ़ी तो शहरों का रंगरूप बदल गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा की अब नोएडा को देखिए, यहाँ की आईटी कंपनियों, स्टार्टअप, उद्योगों में बड़ी संख्या में बहन- बेटियाँ और महिलाएं काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर बोलते हुए श्री चौधरी ने कहा कि देश में राज्य में महिलाएँ खूब आगे बढ़ें, सामान्य परिवार की महिलाएँ भी विधायक- सांसद बन सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर आई। क्योंकि हमारा संकल्प है कि सशक्त नारी, समृद्ध समाज, महिला आरक्षण से नया आगाज।विपक्ष के महिला विरोधी आचरण पर बोलते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सपा- कांग्रेस जैसी पार्टियां, जो परिवारवाद की अमर बेल पर फलफूल रही हैं। इन पार्टियों ने इस बिल का विरोध नहीं किया बल्कि इसके पीछे इन्होंने महिलाओं के जीवन में आने वाले ऐतिहासिक बदलाव का विरोध किया है। महिलाओं की सामाजिक मजबूती को डिरेल किया है। उन्होंने कहा की मोदी से नफरत करते ये लोग इतने बदहवास हो चुके हैं कि महिलाओं को उनके हक से वंचित करने का उत्सव मनाने पर उतारू हो गए। इन लोगों को पता है कि महिलाएं संभालेंगी जिम्मेदारी, तो खत्म होगी पारिवारिक यारी। तीन तलाक कानून का जिक्र करते हुए, श्री चौधरी ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के अन्य दलों को आइना दिखाते हुए कहा कि ये लोग मुस्लिम महिलाओं के फर्जी पैरोकार बन रहे हैं। तब मुस्लिम महिलाओं के प्रति इनकी संवदेना कहाँ गई थी जब इन लोगों ने तीन तलाक कानून का विरोध किया। अब सदन में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की माँग कर रहे हैं। यह सिर्फ. इनकी एक चाल थी, क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इन लोगों ने इस बहाने सिर्फ.और सिर्फ.अपनी बांटने वाली मानसिकता का परिचय दिया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के पास न तो नीयत है ना नीति है बस केवल राजनीति है।

श्री चौधरी ने कहा कि सपा- कांग्रेस को दिन- रात सिर्फ. अपने वोट बैंक की फिक्र रहती है। इन्हें महिलाओं के मान- सम्मान और उत्थान से कोई मतलब नहीं है। जब-जब मौका आया ये लोग महिलाओं के विरोध में खड़े मिले हैं। जब जब महिलाओं के उत्थान की बात आई है, इन लोगों ने उसे अटकाने- भटकाने, लटकाने का काम किया है। श्री चौधरी ने परिवारवादी पार्टियों पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इन परिवारवादी पार्टियों को पता है कि देश की राजनीति में एक बार महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी का अधिकार मिल गया, तो इन पार्टियों का अंत सुनिश्चित है। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों के नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध के कारण पर बोलते हुए कहा कि दरअसल इन परिवारवादी पार्टियों के एजेंडे में देश के सामान्य परिवारों, मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि देश के हर वर्ग, हर परिवार की बहन- बेटी की सुरक्षा और समानता के अवसर देने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में है। पंकज चौधरी ने कहा कि महिलाओं की तरक्की का संकल्प पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। प्रेस वार्ता में नोएडा विधायक पंकज सिंह, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी, नवाब सिंह नगर, कैप्टन विकास गुप्ता, सुषमा सिंह, वर्षा यादव, पूनम सिंह, डिंपल आनंद, अमित त्यागी, संजय बाली, शारदा चतुर्वेदी, सुचित्रा कक्कड़, प्रज्ञा पाठक, विजेंद्र नागर, योगेंद्र चौधरी, राकेश शर्मा, विनोद त्यागी, विक्रांत यादव, ओमवीर अवाना चंदगीराम यादव, अशोक मिश्रा, विनोद शर्मा, राजकुमार बंसल, उमेश त्यागी, प्रमोद बहल, राजेंद्र अवाना, पंकज झा, बबलू यादव, मनीष वाल्मीकि, पुष्पा रावत, मीनाक्षी चौहान, धर्मेंद्र गुप्ता, रामकिशन, प्रदीप चौहान, दीनबंधु, नीरज चौधरी, सत्यनारायण महावर, दीपक शर्मा, अनुभूति टंडन, मुक्तानंद शर्मा, विपुल शर्मा, दीपाली दीक्षित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संकुल बैठक में नामांकन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

परसपुर/गोण्डा। विकासखंड परसपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा नोहर में मंगलवार को अप्रैल माह की संकुल बैठक सम्पन्न हुई। अध्यक्षता संकुल प्रभारी अरविंद सिंह ने की। बैठक में विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार चतुवेर्दी ने अप्रैल को नामांकन माह के रूप में मनाते हुए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को भाषा व गणित में निपुण बनाने, शिक्षण सामग्री के उपयोग, तथा बच्चों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रखने के उपायों पर चर्चा हुई। अनुपस्थित बच्चों के घर-घर संपर्क, डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म व अन्य सुविधाओं की धनराशि समय से भेजने हेतु प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह ने अप्रैल को सत्र की नींव बताते हुए सभी शिक्षकों से मेहनत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर लवली यादव, दुर्गा प्रसाद तिवारी, डॉली पाण्डेय,समर बहादुर, सरोज, शारदा प्रसाद, उपेन्द्र बहादुर, इस्लाम खान, सन्तोष कश्यप, पिंकी तिवारी, अनिल सिंह, ललित वर्मा, अखिलेश कुमार, महेश कुमार व रविन्द्र शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

8वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत, आत्महत्या की लगाई जा आशंका

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी में मंगलवार को एक बुजुर्ग की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग कंपनी में नुकसान होने से अवसाद में चल रहे थे। तनाव होने के कारण उन्होंने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन की तरफ से पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। 15 दिन पहले ही वह पत्नी के साथ यहां रहने आए थे। पुलिस ने बताया कि 55 वर्षीय लक्ष्मीकांत जोशी पत्नी मीनाक्षी जोशी के साथ रहते थे। मंगलवार को उन्होंने फ्लैट की बॉलकनी से छलांग लगा दी। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि साल 2008 में केबल बनाने की कंपनी में नुकसान के बाद से वह काफी परेशान रहते थे। वह 5-6 साल से अवसाद की दवा ले रहे थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे हैं।

जिलाधिकारी के अनुमोदन पर चार के विरुद्ध गैंगेस्टर में प्राथमिकी दर्ज

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

हलिया/मिजार्पुर। हलिया थाना क्षेत्र के सोनगढ़ा गांव निवासी चार लोगों के विरुद्ध जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगस्टर में प्राथमिकी दर्ज किया गया हलिया थाना क्षेत्र के सोनगढा गांव निवासी पिंटू, विवेक, आजाद, प्रदीप उर्फ दीपक के विरुद्ध पूर्व में महिला संबंधी अपराध, गैंग लीडर पिंटू का हाफ एनकाउंटर की कार्रवाई किया गया था जिससे चारों आरोपी जेल में बंद है जिसके मद्देनजर समाज में भय का माहौल व्याप्त होने के कारण जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगस्टर अपराध की बढ़ोतरी करते हुए पुलिस गैंगेस्टर की कार्रवाई की है इस संबंध में थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चारों आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं और जेल में बंद हैं जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गैंगस्टर का अपराध दर्ज किया गया है।

लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स एवं बीकमिंग बेटर का ऑनलाइन सत्र आयोजित

नोएडा (स्वास्तिक सहारा)। देश के छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करने और उनकी संचार और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन सत्र (जूम मीटिंग द्वारा) लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स एवं बीकमिंग बेटर हर माह आयोजित किया जाता है। लर्निंग फ्रॉम लीजेंड श्रृंखला सत्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करना और दूसरा उन्हें इस मंच पर बोलने का अवसर देना ताकि उनके सार्वजनिक भाषण कौशल को निखारा जा सके। बीकमिंग बेटर सत्र का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस बार लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स श्रृंखला के अंतर्गत रामनाथ गोयनका की नेतृत्व शैली और उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा की गई। जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खरे की अध्यक्षता में विभिन्न शहरों से आठ चुने हुए विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अनुरीत कौर ने किया। वे बीबी सुरिदर कौर बादल मालवा स्कूल (पंजाब) में कक्षा दसवीं की छात्रा हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब के चुनिंदा विद्यार्थियों ने वक्ता के रूप में भाग लिया। सत्र के सबसे प्रभावशाली वक्ता गुरीत सिंह बराड़ को चुना गया, जो दशमेश पब्लिक स्कूल फरीदकोट (पंजाब) के दसवीं कक्षा के छात्र हैं। इनको मुकेश भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक 'मां शब्द से परे' भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन सभी वक्ताओं को भागीदारी के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र देकर किया गया।

यमुना सिटी में 400 कंपनियां शुरू कर देंगी अपना उत्पादन

ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए कंपनियों में उत्पादन शुरू कराए जाने पर यीडा ने काम शुरू किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 400 कंपनियों में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि यमुना सिटी फेज-1 में 3116 औद्योगिक भूखंड आवंटित हुए हैं। इनमें से 2,708 की चेक लिस्ट जारी की जा चुकी है जिससे लीज डीड की जा सके। इनमें 2,427 उद्यमी लीज डीड करा चुके हैं। अब हमारी प्राथमिकता निर्माण शुरू कराने और यूनिट में उत्पादन शुरू कराने की है। इससे ही निवेश और रोजगार सृजन होगा। वर्तमान में 105 निर्माण पूरे हो चुके हैं जिनके उपभोगिता प्रमाण पत्र जल्दी ही प्राधिकरण जारी कर देगा। 87 निर्माण ऐसे हैं जो कमोबेश पूरे हो चुके हैं। 400 यूनिट के सक्रिय होने से करीब 15 हजार रोजगार यहां सृजित हो जाएंगे।

पीएम मोदी आगमन से पहले काशी में 'मेगा क्लीन मिशन', निगम हाई अलर्ट पर

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए नगर निगम वाराणसी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शहर को स्वच्छ, सुंदर और वीआईपी मूवमेंट के अनुरूप बनाने के लिए निगम प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए एक सप्ताह का व्यापक 'महासफाई अभियान' शुरू कर दिया है। इस अभियान की निगरानी सेंट्रल कमांड से की जाएगी, ताकि शहर के प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था और जनसुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके। सिगरा स्थित स्मार्ट सिटी सभागार में महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने कहा कि शहर की साफ-सफाई और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। महापौर स्वयं आगामी एक सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक अलग-अलग वार्डों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस दौरान संबंधित पार्षदों और अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। नगर निगम ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सभी लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए सात दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। इसके साथ ही शहर के सभी वॉटर एटीएम को सुचारु रूप से संचालित करने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सड़कों, डिवाइडरों और पेड़ों की नियमित धुलाई वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से कराई जाएगी। जलकल विभाग को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी सीवर ओवरफ्लो न हो और सड़कों पर गंदा पानी दिखाई न दे। वहीं, उद्यान विभाग को शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थित मूर्तियों की सफाई, माल्यार्पण तथा आकर्षक गमलों के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य सौंपा गया है। नगर निगम के इस विशेष अभियान से काशी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान शहर की छवि और अधिक बेहतर रूप में सामने आ सके।

जिले के 40 वें जिलाधिकारी के रूप में बद्री नाथ सिंह का सोनभद्र में कार्यकाल रहा सराहनीय

लगभग 22 महीने का रहा ऐतिहासिक कार्यकाल, सोनभद्र जिलाधिकारी से विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पद पर स्थानान्तरित होकर गये

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। कलेक्ट्रेट सभागार में बद्री नाथ सिंह को जनपद सोनभद्र से विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के रूप में स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है, वह समय-समय पर स्थानांतरित होते हुए अलग-अलग स्थानों पर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि मेहनती और ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के समय विदाई के क्षण स्वाभाविक रूप से भावुक कर देते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को यादगार बताते हुए कहा कि जनपद सोनभद्र में कार्य करने के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का जो सहयोग मिला, वह हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध ढंग से किया जाए तो किसी अधिकारी या कर्मचारी पर अनावश्यक मानसिक दबाव नहीं पड़ता और कार्य बेहतर ढंग से संपन्न होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने जनपद में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आई। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने कहा कि एक कर्मठ एवं लगनशील अधिकारी के रूप में बद्री नाथ सिंह ने लगभग 1 वर्ष 10 महीने के कार्यकाल में जनपद को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी कार्यशैली से जटिल समस्याओं का समाधान सरलता से करना सीखा है। कार्यक्रम के दौरान उनके कार्यकाल से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनपद में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे रोहित यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज कुमार राय, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी घोरावल आशीष त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, जिला कृषि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन सुरेश पाठक द्वारा किया गया।

सम्पादकीय

छठे स्थान पर पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण और कुछ हद तक चिंताजनक खबर है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि छठे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान लगभग 4.38 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन 4.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार लगभग 4.15 से 4.17 ट्रिलियन डॉलर के बीच आंका गया है। भारत की रैंकिंग में आई यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपये के कमजोर होने की वजह से मानी जा रही है। रुपया लगभग 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है, जिससे डॉलर में मापी जाने वाली अर्थव्यवस्था का आकार अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज विकास दर है। फिलहाल भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वैश्विक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी तनाव, विशेषकर ईरान से जुड़े संकट के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। यदि आने वाले वर्षों में रुपये की स्थिति मजबूत होती है, तो भारत के 2027 तक फिर से पांचवें स्थान पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चौथे स्थान पर वापसी में कुछ और समय लग सकता है। कई वैश्विक एजेंसियों और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अनुकूल परिस्थितियों में भारत 2030 या 2031 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने अभी कई चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि देश अभी तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य से पीछे है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए अगले एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जोड़ना असंभव नहीं माना जाता। दूसरी चुनौती यह है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय भारत फिलहाल छठे स्थान तक खिसक गया है और फ्रांस भी उसके करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि रुपये के कमजोर होने से आयातित वस्तुएं—जैसे कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोकेमिकल उत्पाद—और महंगे हो सकते हैं। इससे देश में महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल मुद्रास्फीति लगभग 4.6 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4 से 5 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है। भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का लगभग 55.6 प्रतिशत बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में आई इस गिरावट का असर निवेशकों की धारणा पर भी पड़ सकता है।

छात्रों का आत्मघात: सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी?

ललित गर्ग

कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में दो महीनों के भीतर चार छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केवल एक संस्थान की त्रासदी एवं नाकामी नहीं हैं, बल्कि पूरे भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता पर लगा गहरा प्रश्नचिह्न हैं। ये घटनाएं हमें झकझोरती हैं कि आखिर वह कौन-सी परिस्थितियां हैं, जिनमें देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं जीवन से हार मानने को विवश हो जाती हैं। कोई भी युवा, जो कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरकर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचता है, वह सहज रूप से जीवन का परित्याग नहीं करता, वह तब यह निर्णय लेता है जब उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत विफलताओं का सम्मिलित परिणाम है। एक बड़ा सवाल है कि इस तरह छात्रों का आत्मघात करना क्या सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी? आज भारत का भविष्य कहे जाने वाले युवा जिस मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं, वह अभूतपूर्व चिन्ताजनक है। कोटा जैसे शिक्षा नगरों में हर वर्ष दर्जनों छात्र आत्महत्या करते हैं। इन घटनाओं को हम आंकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक जीवित सपना, एक संघर्षरत परिवार और टूटती उम्मीदों की कहानी होती है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य शिक्षा केंद्रों में बढ़ती आत्महत्याएं इस बात का संकेत हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं। यह केवल पढ़ाई का दबाव नहीं है, यह उस मानसिक संरचना का संकट है, जिसमें सफलता को जीवन का पर्याय बना दिया गया है और असफलता को जीवन का अंत।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक घटनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुईं, इसके बाद एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान है। यह तथ्य इस धारणा को तोड़ता है कि केवल कमजोर छात्र ही मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे प्रतिभाशाली और संवेदनशील छात्र ही अक्सर सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। यहां प्रश्न केवल संस्थानों का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का भी है जिसने सफलता को एक संकीर्ण परिभाषा में बांध दिया है। परिवार अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है। अभिभावक अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के मन पर इतना भारी पड़ता है कि वे स्वयं को एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, एक इंसान की तरह नहीं। जब यह प्रोजेक्ट असफल होता है, तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है।

शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी इस संकट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को ज्ञान तो देती है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। उन्हें बताया जाता है कि गणित कैसे हल करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। उन्हें भौतिकी के नियम याद कराए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है। परिणामस्वरूप, जब वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से सामना करते हैं तो वे टूट जाते हैं। आज के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध भी बदल गया है। पहले शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक होते थे। आज यह संबंध औपचारिक हो गया है। कई शिक्षक अपनी भूमिका को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखते हैं। वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके भावनात्मक संघर्षों और उनके आंतरिक द्वंद्व को समझने का प्रयास नहीं करते। यह दूरी छात्रों को और अधिक अकेला बना देती है।

विचित्र है कि जो देश दुनिया भर में अपनी संतुलित जीवनशैली एवं अहिंसा के लिये जाना जाता है, वहां के शिक्षा-संस्थानों में हिंसा का भाव पनपना एवं छात्रों के आत्महंता होते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों एवं खौफनाक दुर्घटनाओं के आंकड़ों ने शासन-व्यवस्था के साथ-साथ समाज-निमार्ताओं को चेताया है और गंभीरतापूर्वक इस विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक समस्या पर विचार करने के लिये जागरूक किया है, लेकिन क्या कुछ सार्थक पहल होगी? बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपनी कार्यशैली एवं परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन करें ताकि छात्रों पर बढ़ते दबावों को खत्म किया जा सके। फिलहाल जरूरी यह भी है कि इन संस्थानों में एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जाए, जो निराश, हताश और अवसादग्रस्त छात्रों के लगातार संपर्क में रहकर उनमें आशा का संचार कर सके, उन्हें सकारात्मकता के संस्कार दे सके। इसके लिए स्थाई तौर पर कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल जांच समितियां बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समितियां रिपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन वे खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचें और उसे दूर करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपाय करें। छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को केवल मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानना भी पर्याप्त नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक संकट है, जिसमें शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संरचना, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत मनोविज्ञान सभी शामिल हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहां सफलता की अंधी दौड़ ने मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया है। यहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि इस दौड़ में पीछे छूटने वाले भी इंसान हैं। इस समस्या का समाधान केवल नीतिगत बदलावों से नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें शिक्षा की परिभाषा को बदलना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरूआत है।

दूसरे, अभिभावकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि वे उनसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, न कि उनकी सफलता। उन्हें बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तीसरे, शिक्षण संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझना होगा। उन्हें केवल

दैनिक राशिफल

मेष: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

निवेश के सुखद परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ: इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।

कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। व्यस्तता रहेगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।

मिथुन: का, की, कु, घ, ङ:, छ, के, को, हा।

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा।

कर्क: ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।

कारोबार में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। धनार्जन होगा।

सिंह: मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।

कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा।

कन्या: टो, पा, पी, पू, ष, ण:, ठ, पे, पो।

धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता होगी। ऐश्वर्य पर व्यय होगा।

तुला: रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।

जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे।

वृश्चिक: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे।

धनु: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

मकर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।

आज लेन-देन में विशेष सावधानी रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दु:खद समाचार मिल सकता है।

कुंभ: गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।

पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी।

मीन: दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म, नई दिल्ली
मो. नं.: +91 99990 74369
ओमीलाल वर्मा (एडवोकेट)
मो. नं.: 98109 03664

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road, Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

ग्रामीण भारत के 30% स्कूलों में मैदान नहीं, कहीं झाड़ियाँ उगीं तो कहीं दबंगों का कब्जा

भारत भूषण अड़जरिया

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है, जहाँ की मिट्टी ने मिल्खा सिंह, पी.टी. उषा और नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में खेलों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विभिन्न शिक्षा रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों (जैसे यूडीआईएसई+) के अनुसार, आज भी लगभग 30 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों के पास अपना स्वयं का खेल का मैदान नहीं है। जहाँ मैदान उपलब्ध भी हैं, वहाँ उनका रखरखाव इतना खराब है कि वे खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित नहीं माने जा सकते। बाउंड्री वॉल का न होना, मैदान में झाड़ियाँ उगना या स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करना एक आम समस्या बन गई है, जिसके कारण बच्चों को सड़कों या संकरी गलियों में खेलने को मजबूर होना पड़ता है।

संसाधनों की यह कमी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि उपकरणों के स्तर पर भी काफी चिंताजनक है। बजट का अभाव ग्रामीण विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा का अधिकांश बजट शिक्षकों के वेतन और मिड-डे मील जैसी अनिवार्य योजनाओं में ही समाप्त हो जाता है, जिससे खेलों के लिए नगण्य राशि बचती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक बड़े प्रतिशत स्कूलों में खेल के नाम पर केवल एक फटी हुई फुटबॉल या कुछ पुराने क्रिकेट बैट ही होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए आवश्यक नेट, पोल और ट्रैक तो ग्रामीण भारत के अधिकांश विद्यालयों के लिए आज भी एक विलासिता जैसे हैं। इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद एक और गंभीर संकट हैं। देश के लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों को खेलों की बारीकियों और नियमों की जानकारी नहीं मिल पाती। बिना सही मार्गदर्शन के, प्रतिभाशाली बच्चे भी जिला या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

सामाजिक और नीतिगत स्तर पर भी ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को वह सहयोग नहीं मिल पाता जिसकी वे हकदार हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब' वाली कहावत हावी है, जहाँ खेलों को पढ़ाई में बाधा माना जाता है। केंद्र सरकार की 'खेलो इंडिया' जैसी योजनाएं निस्संदेह सराहनीय हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ अभी भी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटा हुआ है। ग्रामीण ब्लॉकों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद सुस्त है। संसाधनों के इस अभाव का सीधा परिणाम ग्रामीण युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। खेलों की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर होकर मोबाइल गेमिंग और डिजिटल व्यसनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यदि भारत को वास्तव में एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनना है, तो हमें अपनी नीतियों के केंद्र में ग्रामीण विद्यालयों को रखना होगा। जब तक गाँव के हर स्कूल में एक समतल मैदान, आवश्यक खेल उपकरण और एक समर्पित कोच की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक 'फिट इंडिया' और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना अधूरा ही रहेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर बजटीय आवंटन बढ़ाना और निजी क्षेत्रों को खेल बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।

ईरान की ताकत बरकरार, अमेरिका के घटे हथियार! क्या इसी वजह से ट्रंप ने बढ़ाया युद्धविराम?

नीरज कुमार दुबे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्षविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला उस समय लिया गया जब संघर्षविराम समाप्त होने में कुछ ही घंटे बाकी थे और हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे थे। ट्रंप ने कहा कि यह कदम ईरान को एक साझा और स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करने का समय देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। ट्रंप ने भी अपने संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका का जिक्र किया।

हालांकि, संघर्षविराम के ऐलान के बावजूद जमीन पर हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी जारी रखी है और अपनी सैन्य तैयारियों को बरकरार रखा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वह धमकियों और दबाव के माहौल में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस बीच, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जारी रखे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। गाजा में भी हमले जारी हैं, जिससे क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा गया है। इस स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघर्षविराम केवल कागजी राहत है, जबकि वास्तविकता में तनाव बना हुआ है। राजनयिक स्तर पर भी स्थिति उलझी हुई है। इस्लामाबाद में बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के नहीं पहुंचने से आंतरिक मतभेदों के संकेत मिल रहे हैं। चीन ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए हस्तक्षेप किया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की मांग की है।

अब यदि अमेरिकी रक्षा विभाग की खुफिया शाखा के ताजा आकलन की बात करें, तो यह तस्वीर और जटिल हो जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब भी अपनी प्रमुख सैन्य क्षमताएं बनाए हुए है और वह एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बना हुआ है। यह आकलन उन दावों के विपरीत है, जिनमें कहा गया था कि ईरान की सैन्य ताकत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है।

खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की वायु और नौसेना पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है और उसकी रणनीतिक क्षमता अभी भी प्रभावी बनी हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका के सार्वजनिक बयान और वास्तविक स्थिति में अंतर है। यह अंतर भविष्य की रणनीति और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

इसी बीच, एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिसने अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रक्षा विश्लेषकों और पेंटागन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ईरान के साथ सात सप्ताह तक चले संघर्ष में अमेरिका ने अपने कई महत्वपूर्ण मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका ने अपने प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का लगभग 45 प्रतिशत, थाड इंटरसेप्टर का लगभग आधा और पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों का करीब 50 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल का लगभग 30 प्रतिशत और अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों का भी बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है।

वैश्विक औसत से बहुत दूर है सत्ता में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी और विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताई है। हांलाकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर यह अलग बहस का विषय हो सकता है। पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामलें में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विष्लेषण करे तो हमारे देश का स्थान 147 वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी और करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक महिलाओं की बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रौचक बात यह है कि 2009 की 15 वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15 वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हांलाकि 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपातकाल के बाद की स्थितियां थी। 18 वीं लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही।

जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्य सभा में टीएमसी दल की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है। त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य है। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। नागालैंड देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम महिला सदस्य है। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य है।

खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती है। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि बिना आरक्षित सीटों के विधानसभाओं या संसद में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की कल्पना करना बेमानी होगी। यह तो संवैधानिक बाध्यता से ही संभव हो पाएगा। यह सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा।

यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

सड़क पर मौत का साया और फाइलों में विकास– एनएच 39 पर राजनीति और प्रशासन दोनों बेनकाब

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जनपद के विंढमगंज-दुद्धी-हाथीनाला-रेनुकोट मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसे अब सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं बल्कि यह उस सरकारी व्यवस्था की असल तस्वीर हैं जहाँ जनता सड़क पर मरती है और विभाग फाइलों में विकास ढूंढता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले लोगों के लिए यह मार्ग अब राष्ट्रीय राजमार्ग कम और मौत का मार्ग ज्यादा बन चुका है। विभागीय आख्या में मरम्मत पैंचवर्क, गड्ढा भराई रोड सेफ्टी ऑडिट और चार लेन प्रस्ताव जैसी बातें गिनाई जा रही हैं। कागजों में सब कुछ व्यवस्थित और प्रगतिशील दिखाया जा रहा है लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। सड़क पर गड्ढे अब भी हैं हादसे अब भी हो रहे हैं और लोग अब भी असुरक्षित हैं। यानी सरकारी फाइलों में सड़क चमक रही है लेकिन हकीकत में जनता की जिंदगी अंधेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग को पता है कि अनपरा हिंडाल्को और सिंगरौली क्षेत्र के भारी वाहनों का दबाव इस सड़क को तोड़ रहा है, तो अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ क्या विभाग हादसों के बाद जागने की परंपरा निभा रहा है। क्या लोगों की जान की कीमत केवल एक आख्या भर है राजनीतिक स्तर पर भी तस्वीर कम शर्मनाक नहीं है। चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं–सड़क सुरक्षा सुविधा के सपने दिखाए जाते हैं लेकिन जब उन्हीं सड़कों पर जनता की जान जाती है तब जिम्मेदारी केवल फाइलों और प्रस्तावों में सीमित रह जाती है। नेताओं के भाषणों में विकास दौड़ता है लेकिन जमीन पर एंबुलेंस और शववाहन। यदि सड़क की हालत खराब है तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती यदि भारी वाहनों से मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है तो नियंत्रण क्यों नहीं होता यदि हादसे लगातार हो रहे हैं तो विभागीय जवाबदेही केवल कार्य प्रगति पर है कहकर खत्म कैसे हो जाती है दरअसल यह केवल सड़क का मामला नहीं है यह प्रशासनिक संवेदनहीनता और राजनीतिक दिखावे का उदाहरण है। जब तक हादसों को आंकड़ों की तरह देखा जाएगा तब तक समाधान भी कागजों तक सीमित रहेगा। जनता को राहत नहीं सिर्फ आश्वासन मिलेगा सुरक्षा नहीं सिर्फ बयान मिलेंगे। अब वक्त है कि जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाए कि आखिर एनएच-39 पर विकास कब उतरेगा कब तक सड़कें जान लेती रहेंगी और विभाग प्रस्ताव भेजने की औपचारिकता निभाता रहेगा कब तक जनता की मौत पर राजनीति अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी क्योंकि सड़क पर हर हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं होता वह व्यवस्था की विफलता का प्रमाण होता है। अगर सड़क पर मौत जारी है तो समझ लीजिए विकास सिर्फ भाषणों में जिंदा है।

शिक्षा जगत में काशी की गूंज: प्रो. रमाशंकर दूबे बने नीपा के कुलाधिपति, देश को मिलेगा अनुभवी नेतृत्व

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। शिक्षा और अकादमिक जगत के लिए गर्व का क्षण है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग के पूर्व प्रोफेसर प्रो. रमाशंकर दूबे को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा) का कुलाधिपति (चांसलर) नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार यह महत्वपूर्ण नियुक्ति केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए की गई है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैव रसायन वैज्ञानिक और कुशल शिक्षाविद के रूप में पहचान रखने वाले प्रो. दूबे का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव अत्यंत समृद्ध रहा है। वे पूर्व में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (बिहार) तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (बिलासपुर, छत्तीसगढ़) के कुलपति के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी यह नई जिम्मेदारी देश में शैक्षिक योजना, प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि नीपा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक अग्रणी मानित विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा नीति, योजना और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रो. दूबे की नियुक्ति से न केवल संस्थान बल्कि पूरे शिक्षा जगत को एक अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सोनभद्र में आज राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार का दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। प्रदेश के मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग डॉ. अरुण कुमार का जनपद सोनभद्र में आगमन 23 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। उनके दौरे को लेकर प्रशासन एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यापक तैयारियां की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री जी प्रातः 09:30 बजे घोरावल क्षेत्र के ग्राम सरवट पहुंचेंगे, जहां वे मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम-जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के नवनिर्मित मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी सहभागिता करेंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत मंत्री जी प्रातः 11:55 बजे सर्किट हाउस, सोनभद्र में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं के साथ बैठक कर क्षेत्रीय विकास, संगठनात्मक गतिविधियों एवं जनसमस्याओं पर चर्चा करेंगे।

दोपहर बाद 04:10 बजे वे वन विभाग के सभागार में वन विभाग, वन निगम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण नियंत्रण एवं विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री जी रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, चुर्क में करेंगे। इसके पश्चात 24 अप्रैल 2026 को प्रातः 07:00 बजे वे अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। मंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क है और सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मोहित माधव की उपस्थिति में गूंजा नारी शक्ति का दम: दिल्ली क्वींस कबड्डी चैंपियनशिप में दिखा भारत का गौरव

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय पारंपरिक खेलों की ऊर्जा और नारी शक्ति का भव्य संगम दिल्ली क्वींस कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के रूप में देखने को मिला। 17 से 19 अप्रैल तक स्वामी विवेकानंद पार्क में आयोजित इस प्रतियोगिता ने राजधानी में खेल प्रेमियों के बीच विशेष उत्साह का वातावरण निर्मित किया। यह आयोजन देश की चुनिंदा महिला कबड्डी प्रतियोगिताओं में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे मोहित माधव, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कबड्डी भारत की आत्मा से जुड़ा खेल है, जो अनुशासन, साहस और टीम भावना का प्रतीक है। उन्होंने विशेष रूप से युवतियों को पारंपरिक खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उनके साथ डॉ. अतासी मिश्रा भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा खेल और आयोजन से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और सशक्त बनाया। प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से प्रारंभ हुए मुकाबलों में शाहदरा शेरनिस, रोहिणी रानिस, मेहरौली मिरेकल्स, नजफगढ़ निंजाज, गाजीपुर गार्डियंस, द्वारका दुर्गाज, बदरपुर ब्लास्टर्स और भजनपुरा भावन्स जैसी टीमों ने अपने शानदार खेल से दर्शकों का मन मोह लिया। यह चैंपियनशिप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, नारी सशक्तिकरण और युवा ऊर्जा का सशक्त प्रतीक बनकर उभरी।

सड़क के बीच खंभे, बढ़ा हादसों का खतरा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-2 में इरोस संपूर्णम सोसाइटी के सामने बनी नई सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन गई है। सड़क निर्माण के दौरान बीचों-बीच बिजली के खंभे छोड़ दिए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक स्थान पर खंभा सड़क के बिल्कुल बीच में है, जबकि दूसरी जगह दो खंभों के बीच से सड़क निकाली गई है। इससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों दोनों के लिए जोखिम बना हुआ है।

गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष रश्मि पांडेय ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस कार्य को मंजूरी देना चिंताजनक है। वहीं उपाध्यक्ष हिमांशु राजपूत ने कहा कि यह मार्ग भविष्य में प्रमुख रास्ता बनेगा, ऐसे में कोहरे के दौरान हादसों का खतरा और बढ़ जाएगा। समिति ने मांग की है कि खंभों को जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

दो बाइकों की टक्कर में युवक गंभीर घायल, ट्रामा सेंटर रेफर

हलिया/मिजार्पुर (स्वास्तिक सहारा)। हलिया थाना क्षेत्र के हलिया–लालगंज मार्ग स्थित बसुहरा गांव के पंचायत भवन के पास बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दो बाइकों की आमने–सामने टक्कर में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हलिया थाना क्षेत्र के देवघटा पांडे गांव निवासी अवधेश कुमार बिंद मंगलवार शाम बसुहरा गांव में अपनी बहन राधा कुमारी के यहां विवाह समारोह में शामिल होने आया था। बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह हलिया–लालगंज मार्ग पर मुख्य सड़क पर पहुंचा, सामने से आ रहे एक अज्ञात बाइक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अवधेश कुमार बिंद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. आलोक सिंह यादव ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए घायल को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

आईएमएस नोएडा में आईटी एक्सपो का आयोजन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। सेक्टर 62 स्थित आईएमएस नोएडा में आईटी एक्सपो का आयोजन हुआ। बुधवार को कार्यक्रम के दौरान एमसीए एवं बीसीए के छात्रों ने 32 स्टॉल लगाए। कार्यक्रम की शुरूआत आईबीएम की आइडेंटिटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजर रितु मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान 25 से अधिक कंपनियों ने प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। आईएमएस स्कूल ऑफ आईटी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि आज आईटी एक्सपो के दौरान ऐप्सक्वाज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट एनर्जी वाटर, एमवीडी टेक्नोलॉजी, एलआरपी कैप्टिवेटर प्राइवेट लिमिटेड, आईबीएम सॉफ्टवेयर, स्टेफनी इंडिया, स्विफ्टकी, किंडवेल, गैलेक्सी इन्फोटेक एवं अन्य आईटी कंपनी के प्रतिनिधियों नेअपनी उपस्थिति दर्ज करायी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। इस प्रोजेक्ट शो-केस सत्र में 70 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने नवाचारपूर्ण एवं तकनीकी प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। आईबीएम की सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजर रितु मित्तल ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट्स वर्तमान उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। उन्होंने छात्रों की तकनीकी समझ, नवाचार क्षमता और समस्या समाधान कौशल की प्रशंसा की। रितु मित्तल ने बताया कि विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से व्यावहारिक सोच और आधुनिक तकनीकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अति विशिष्ट, उपयोगी एवं प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स वाले छात्रों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. अनिता पति मिश्रा ने बताया कि आज का आयोजन विद्यार्थियों के कौशल, नवाचार क्षमता एवं उद्योग जगत से जुड़ाव के लिए आयोजित किया।

प्रशिक्षण वर्ग को लेकर विधायक अजय सिंह के कार्यालय में हुई बैठक

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

परसपुर गोण्डा। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सिंह के कार्यालय आटा परसपुर में मंगलवार को प्रशिक्षण वर्ग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक तैयारियों एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह एवं वंदना गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि सूरज सिंह,इतेंद्र सिंह गुड्डू,प्रदीप तिवारी,आनन्द शुक्ला उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, वर्ग प्रभारी एवं वर्ग प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता रही। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा, संगठन की मजबूती तथा कार्यकताओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। मण्डल अध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग संगठन को नई ऊर्जा देने का कार्य करेगा और इससे कार्यकताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

अज्ञात कारणो से सिवान मे लगी आग दस बीघे खेत तक फैली, ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

हलिया/मिजार्पुर। हलिया थाना क्षेत्र के बसुहरा गांव में बुधवार को दोपहर में 12 बजे के करीब अज्ञात कारणों से खेत में रखें भूसे तथा पुआल में आग लग गई देखते ही देखते आग तेजी से फैलते हुए सिवान के दस बीघे तक हार्वेस्टर से कटे गेहूं के डंठलों को अपनी चपेट में ले लिया अगल-बगल के लोगों द्वारा शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डब्बा बाल्टी तथा समर सेबल पंप की मदद से आग पर काबू पाया बसुहरा गांव निवासी रामप्यारे तिवारी के घर के बगल में रखे उनके चार बीघा के पुआल में अज्ञात कारणों से आग लग गई परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते आग बगल में रखें चार बीघे भूसे में भी लग गई तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए रंजीत पांडे तथा सुरेश पांडे के घर तक पहुंच गई मौके पर पहुंचे ग्रामीण जब तक आग बुझाने का प्रयास करते आग तेजी से फैलते हुए सिवान के लगभग दस बीघा हार्वेस्टर से कटे हुए गेहूं के डंठलों को अपनी चपेट में ले लिया ग्रामीणों ने डब्बा बाल्टी तथा समर सेबल पंप की मदद से घंटो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया गया होता और आग पूरब दिशा की जगह दक्षिण दिशा की तरफ फैलती तो बस्ती होने के चलते काफी नुकसान हो जाता अगलगी की घटना में राम प्यारे तिवारी का सिंचाई की दस प्लास्टिक पाइप तथा चार बीघे का भूसा एवं चार बीघे का पुआल जलकर राख हो गया आग बुझने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

भगवान की अनुभूति इंद्रियों से होने पर मिलती है भगवत प्राप्ति: विष्णु धर द्विवेदी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

हलिया/मिजार्पुर। विकासखंड हलिया के हथेड़ा गांव में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिवस बुधवार को कथा व्यास पंडित विष्णु धर द्विवेदी जी ने बताया कि जब तक भगवान कारागार में थे तब तक दुनिया को आनंद नहीं आया और जब वही भगवान इंद्रिय रुपी गोकुल में आ गए तो संपूर्ण विश्व में आनंद की लहर दौड़ गई ,जब भगवान अंतरंग में रहेंगे तो आनंद आने वाला नहीं है, भगवान की अनुभूति इंद्रियों में होनी चाहिए, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। कथा वाचक ने कहा कि पूतना भगवान को लेकर भागी जो अविद्या है जब मानव मात्र के शरीर में प्रवेश करती है तब वह मनुष्य को बहुत सुंदर लगती है, जब वही अविद्या विकराल रूप धारण कर लेती है तो पूतना जैसी हो जाती है जो अत्यंत कष्ट कारक बनती है। भगवान कृष्ण की गोकुल, वृंदावन, मक्खन लीलाएं, गोवर्धन की लीला का विस्तृत वर्णन किया। कहा कि जब तक धरा धाम पर पहाड़ है, वृक्ष है, तभी तक बरसात है, तभी तक जीवन है और जब धरा धाम पर सारे पेड़ कट जाएंगे, तब दुनिया के लोग पहाड़ को बेच कर खा जाएंगे, तो आक्सीजन की कमी होगी, तब तपन बढ़ जाएगी बरसात कम होगी जैसा कि इस समय पर अप्रैल के महीने में ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसका मात्र एक ही कारण है सड़क के किनारे लगे हुए सारे वृक्ष सरकार ने कटवा करके फोर लाइन बना दिया, सारे पेड़ कट गए जिससे प्रचंड गर्मी का मानव मात्र को सामना करना पड़ रहा है यदि आने वाले दिनों में हर प्राणी पांच पेड़ नहीं लगाएगा तब तक मानव मात्र का कल्याण नहीं होगा। इस अवसर पर शिवकुमारी देवी, लक्ष्मीकांत मिश्रा, शिवाकांत मिश्रा, सिद्ध दत्त तिवारी प्रमोद दत्त तिवारी आदि सहित सैकड़ों श्रोता भक्त कथा सुन भाव विभोर हो गए।

जाटौली मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू, अटल किसान कैंटीन को मंजूरी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

मनोज मोकलवास
चेयरमैन मार्केट कमेटी

पटौदी (गुरुग्राम)। नई अनाज मंडी जाटौली में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से जहां सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, वहीं अब मंडी में अटल किसान कैंटीन बनाने की भी मंजूरी मिल गई है। मार्किट कमेटी के चेयरमैन मनोज मोकलवास ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एवं केबिनेट मंत्री आरती राव के प्रयासों से यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस कार्य में विधायक बिमला चौधरी तथा जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी विनय यादव का भी सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि कैंटीन बनने से मंडी में आने वाले किसानों और मजदूर भाइयों को सस्ता एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें भोजन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसी के साथ मंडी में सरसों की सरकारी खरीद भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। यह कार्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा के निर्देशन एवं उपायुक्त उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उपमंडल अधिकारी (ना०) पटौदी दिनेश, विधायक बिमला चौधरी, विनय यादव तथा मार्किट कमेटी के सचिव विपिन यादव की उपस्थिति में खरीद प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल रही है। मंडी में किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, बायोमैट्रिक सत्यापन तथा सहायता केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहले दिन 5 किसानों से 94 क्विंटल सरसों की खरीद की गई।

किसानों ने बताया कि मंडी में व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। व्यापार मंडल प्रधान अजय मंगला ने कहा कि विपणन बोर्ड के कर्मचारी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। मंडी के अनुसार अब तक गेहूं की 3,59,032 क्विंटल खरीद तथा 1,44,809 क्विंटल उठान किया जा चुका है। रबी सीजन के दौरान सरसों की 19,211 क्विंटल निजी खरीद भी हो चुकी है, और अब सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों को और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। जाटौली मंडी में एक ओर जहां खरीद व्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं अटल किसान कैंटीन की मंजूरी से किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

खंड विकास अधिकारी ने एलडीएम संग बैठक कर बैंक खाते के संबंध में की चर्चा

हलिया मिजार्पुर (स्वास्तिक सहारा)। ब्लाक सभागार हलिया में बुधवार को खंड विकास अधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी एलडीएम आनन्द कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक कर विकास खंड के समस्त साखा प्रबंधक व ब्लाक मिशन मैनेजर,एडीओ आरडी,सीएम फेलो व बैंक सखियों को दिशा निर्देश देते हुए बताया कि क्षेत्र के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं किसानों के हित व सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी बैंक खातों में आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के साथ तत्काल निदान करें और जिसका बैंक खाता न खुला हो उसका खाता खोलने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें समय से उनके समस्या का समाधान करें जिससे किसानों को बार बार बैंक का चक्कर लगाने के लिए परेशान न होना पड़े इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के खाते को प्राथमिकता के साथ समय से खोलें इसमें लापरवाही न बरतें इसके बाद मुख्यमंत्री युवा योजना के अधिक से अधिक खाता खोलने के लिए प्रेरित किए एवं आवश्यक दिशा–निर्देश दिए इस दौरान हरिओम बिंद, सीएम फैलो गौरव सिंह, भूपेंद्र कुमार शुक्ला, अखिलेश यादव, ओमप्रकाश, राम दयाल, सुषमा, कुसुम, सीमा सहित समूह की महिला उपस्थित रही।

गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में गरजे मुख्यमंत्री

कांग्रेस-सपा महिला विरोधी: सीएम योगी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दल महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा के इतिहास व उनके कारनामों को महिला विरोधी बताया। उन्होंने बुधवार शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का स्वतः अधिकार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को कानून बनाने में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के इतिहास और परंपरा में मातृशक्ति सदैव प्रतिष्ठित रही है। उन्होंने भगवान राम को कौशल्यानंदन और प्रभु कृष्ण को यशोदानंदन कहे जाने का उदाहरण दिया। श्रीराम में श्री शब्द माता सीता के लिए है और सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा भी पहले माता सीता का नाम जोड़कर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण की धरा मथुरा-वृंदावन में हर संबोधन राधे-राधे से शुरू होता है। काशी में नमः पार्वती पतये का उद्घोष होता है और गंगा जी को मां गंगे कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी गरिमा को हर स्तर पर सम्मान देने का काम शुरू हुआ है।

उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी पहल का उल्लेख किया, जिससे 26 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए मातृ वंदना और इंद्रधनुष योजना जैसे कार्यक्रम चलाए। प्रदेश में बाल विवाह और दहेज रोकने के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना, घरौनी, शौचालय, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री स्वनिधि और आयुष्मान योजना में महिलाओं को सर्वाधिक भागीदारी मिली है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी रैली का संस्मरण साझा किया, जहां हजारों नारी शक्ति ने भाजपा का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि डबल इंजन की सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम योगी ने विपक्षी दलों को घेरा

उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों और वंचितों के अधिकार में हमेशा बाधा डाली। उन्होंने सपा को घोषित रूप से नारी विरोधी बताते हुए कहा कि देख सपाई, बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के पहले सपा सरकार में बेटियों को स्कूल भेजना बंद हो गया था। अब बेटियां बिना रोक-टोक स्कूल जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद पुलिस में 44 से 45 हजार महिलाओं की भर्ती हुई है, जबकि पहले यह संख्या केवल 10 हजार थी। अब पुलिस भर्ती में 20 फीसदी महिलाओं की भर्ती अनिवार्य कर दी गई है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिला है। राज्य में 54 फीसदी ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं। ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में भी महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के बाद नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में पौने दो लाख महिलाएं भर्ती हुई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, जिसमें आधी भागीदारी महिलाओं की है।

ईको पार्क संग 470 विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात, स्वच्छ स्कूल अभियान का शुभारंभ करेंगे योगी

गोरखपुर। लोकार्पण और शिलान्यास के लिए समारोह का आयोजन एकला बांध पर विकसित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जनता को समर्पित होने जा रहे ईको पार्क में होगा। यह पार्क जहां बनाया गया है, वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव बताते हैं कि नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करने के बाद कूड़ा मुक्त हुई 40 एकड़ भूमि को ईको पार्क के रूप में विकसित कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को ईको पार्क सहित 470 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम, करीब 1054 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें ईको पार्क के सामने सड़क सहित 173 विकास कार्यों का लोकार्पण और सीएम ग्रिड के तहत 6 स्मार्ट सडकों समेत 297 कार्यों का शिलान्यास शामिल है।

लोकार्पण और शिलान्यास के लिए समारोह का आयोजन एकला बांध पर विकसित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जनता को समर्पित होने जा रहे ईको पार्क में होगा। यह पार्क जहां बनाया गया है, वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव बताते हैं कि नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करने के बाद कूड़ा मुक्त हुई 40 एकड़ भूमि को ईको पार्क के रूप में विकसित कर दिया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ईको पार्क बनाने में करीब 5 करोड़ रुपये की लागत आई है। ईको पार्क में वाकिंग ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं, जहां लोग सुबह और शाम सैर कर सकेंगे। योग और ध्यान के लिए अलग स्थान हैं। बच्चों के लिए भी सुरक्षित किड्स जोन का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री, गुरुवार को ही एकला बंधा पर 8.35 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य, राजघाट पुल से कारकस प्लांट तक 7.71 करोड़ रुपये से कराए गए सड़क सुधार कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। 304.68 करोड़ रुपये की लागत से लोकार्पित होने वाले 173 कार्यों में विभिन्न वार्डों में सड़क व नाली निर्माण के 87 कार्य (लागत 95.77 करोड़ रुपये), जल निकासी के लिए नाला निर्माण के 83 कार्य (लागतन 129.85 करोड़ रुपये) तथा 58 करोड़ रुपये के महापौर/पार्षद वरीयता कार्य शामिल हैं।

सीएम ग्रिड की स्मार्ट सड़कों का होगा विस्तार

समारोह स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ग्रिड (चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) योजना के तहत स्मार्ट सड़कों के विस्तार को भी गतिमान करेंगे। वह सीएम ग्रिड के तहत स्मार्ट बनने जा रही 6 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम ग्रिड तृतीय चरण में 45.68 करोड़ रुपये से गणेश चौक से विश्वविद्यालय चौक एवं अलंकार ज्वेलर्स से एचपी स्कूल, डीएम आवास होते हुए हरिओम नगर तिराहा तक, 23.43 करोड़ रुपये से स्पोर्ट्स कॉलेज रोड से जायसवाल मार्ट होते हुए पुलिया तक तथा 21.60 करोड़ रुपये से कचहरी चौक से शास्त्री चौक होते हुए बेतियाहाता चौक सड़क को स्मार्ट बनाया जाएगा। जबकि तृतीय अनुपूरक चरण में 63.94 करोड़ रुपये की लागत से बेतियाहाता चौक से अलहदादपुर तिराहा, टीडीएम तिराहा से टीपीनगर तक एवं रैन बसेरा रोड से एनएच 28 तक, 62.94 करोड़ रुपये से टीडीएम तिराहा से पांडेयहाता पुलिस चौकी होते हुए बर्फखाना रोड से हार्बट बंधा तक और 25.45 करोड़ रुपये से अलहदादपुर तिराहा से रायगंज होते हुए घंटाघर तक सड़क का कायाकल्प किया जाएगा।

शिलान्यास की अन्य प्रमुख परियोजनाएं

उपवन योजना के तहत तीन पार्कों का सौंदर्यीकरण, लागत 6.44 करोड़ रुपये। विभिन्न वार्डों में जलनिकासी के लिए नाला निर्माण के 83 कार्य, लागत 107.44 करोड़ रुपये। गुलरिहा थाने से चिलुआताल तक आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण, लागत 123.81 करोड़ रुपये। विभिन्न वार्डों में ग्रीन बेल्ट एवं मिनी फॉरेस्टेशन के कार्य, लागत 35.01 करोड़ रुपये। ईको पार्क एवं फोरलेन सड़क के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छ स्कूल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। यह अभियान, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सिटी लीडरशिप का विशेष कार्यक्रम है। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव का कहना है कि स्वच्छ स्कूल अभियान केवल स्वच्छता का कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि यह आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी माध्यम है। वच्छ

लखनऊ में 24 को आयोजित होगी 'जोनल कान्फ्रेन्स-2026'

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में जुटेंगे कई राज्यों के कृषि मंत्री

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 'द सेंट्रम होटल' में आगामी 24 अप्रैल, 2026 को 'जोनल कान्फ्रेन्स-2026' का आयोजन किया जाना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस जोनल कान्फ्रेन्स में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के माननीय कृषि मंत्रीगण प्रतिभाग करेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ एवं लद्दाख के प्रशासक तथा भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। यह कार्यक्रम 24 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 7:30 बजे तक प्रस्तावित है। पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से कृषि विकास और किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रेस कान्फ्रेन्स और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी साझा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सफल मॉडलों के आदान-प्रदान और क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार किए जाने की भी संभावना है। कार्यक्रम के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, सुझावों और भावी योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में होने वाले संभावित बदलावों की दिशा स्पष्ट हो सके।

डिजिटल ट्रैकिंग से बदली परिषदीय शिक्षा की तस्वीर, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सिस्टम से जुड़े 67 हजार स्कूल

योगी सरकार की सख्त मॉनिटरिंग का असर, रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड में तेज रफ्तार

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था तेजी से डिजिटल, पारदर्शी और परिणामोन्मुख मॉडल की ओर बढ़ रही है। निपुण विद्यालय मूल्यांकन के अंतर्गत प्रदेश के 01 लाख 06 हजार से अधिक विद्यालयों का आकलन किया गया, जिनमें से 67 हजार 200 (21 अप्रैल तक) से अधिक विद्यालयों ने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाया है। यह कुल का लगभग 63 प्रतिशत है, जो राज्य में डिजिटल शिक्षा की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता को पुष्ट कर रहा है। यह उपलब्धि बेसिक शिक्षा विभाग की तकनीकी प्रगति का मजबूत संकेत हैं। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। डिजिटल रिपोर्ट कार्ड प्रणाली के माध्यम से अब छात्रों की प्रगति का आकलन अधिक सटीक और त्वरित तरीके से संभव हो रहा है, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद भी सशक्त हुआ है।

डिजिटल रिपोर्ट कार्ड प्रणाली के अन्तर्गत अब विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को पूरी तरह तकनीकी प्लेटफॉर्म पर दर्ज और साझा किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया की जगह पारदर्शी, तेज और प्रभावी व्यवस्था विकसित हुई है। इस प्रणाली में छात्रों के अंक, ग्रेड, उपस्थिति और समग्र प्रगति का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, जिसे अभिभावक कभी भी देख सकते हैं। इससे विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विभाग को वास्तविक समय में मूल्यांकन और निगरानी करने में सुविधा भी मिल रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था ह्यडिजिटल गवर्नेंसह्ण और 'रिजल्ट आधारित मॉनिटरिंग' के नए मानक स्थापित कर रही है। तकनीक के व्यापक उपयोग पर विशेष जोर का ही परिणाम है कि विद्यालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। शिक्षा अब डेटा-आधारित और परिणामोन्मुखी बन रही है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड के मामले में कई जनपदों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर और सिद्धार्थनगर ने 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा संत कबीर नगर (97%), फिरोजाबाद (94%), फतेहपुर (94%), अंबेडकर नगर (93%), चंदौली (91%) और मऊ (90%) ने भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

जालौन (88%), कुशीनगर (87%), कानपुर देहात (86%), गौतम बुद्ध नगर (86%), कासगंज (85%), पीलीभीत (84%), अमेठी (84%), गोंडा (83%), एटा (82%), सुल्तानपुर और हापुड़ (81%) ने उपलब्धि हासिल की है।

स्किल से रोजगार तक, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान

कौशल विकास कार्यक्रमों को सीधे रोजगार से जोड़ने के निर्देश, युवाओं को प्रशिक्षण के बाद तत्काल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को और अधिक प्रभावी एवं परिणामपरक बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कौशल विकास कार्यक्रमों को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण के बाद तत्काल रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि योगी सरकार स्किल डेवलपमेंट को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार मानते हुए इसे उद्योगों से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आईटीआई सुधार, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और आधुनिक कोर्सेज के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के विस्तार को देखते हुए स्किल्ड मैनपावर की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ने की यह पहल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समयबद्ध हों सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम

बुधवार को उत्तर प्रदेश सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट केवल प्रमाण पत्र देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका अंतिम लक्ष्य युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। बैठक में आईटीआई के व्यापक आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण को पूरी तरह इंडस्ट्री-ओरिएंटेड बनाया जाए, जिससे युवाओं को प्रशिक्षण के तुरंत बाद रोजगार मिल सके। इसके साथ ही डिलाइट इंडिया के साथ वर्चुअल प्रेजेंटेशन में नई तकनीकों के अनुरूप स्किलिंग को अपडेट करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में आधुनिक उपकरण, अत्याधुनिक लैब और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके।

ड्रॉपआउट रोकने के लिए ठोस रणनीति

मंत्री अग्रवाल ने कौशल विकास मिशन और आईटीआई में बढ़ते ड्रॉपआउट को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके मूल कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण पूरा कराने के लिए प्रोत्साहन तंत्र विकसित किया जाए। इसके तहत छात्रों के लिए नियमित इंडस्ट्री विजिट, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजीटी) और ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) को बड़े स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी मिल सके।

प्रोजेक्ट प्रवीण और न्यू एज कोर्स पर फोकस

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी आधारित कोर्स शुरू किए जाएं और उन्हें सीधे उद्योगों से जोड़ा जाए।

पृथ्वी दिवस पर छात्रों को दी गयी पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय बिरौंडी चक्रसेनपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पृथ्वी दिवस से संबंधित आकर्षक और संदेशपरक पेंटिंग्स बनाई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि पृथ्वी को प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। छात्र-छात्राओं ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, पानी बचाओ और प्रदूषण मुक्त वातावरण जैसे संदेश प्रस्तुत किए।